

सम्पादकीय

गर्मजोशी के रिश्तों

दिल्ली में संपन्न जी-20 शिखर वार्ता की सफलता से भारत ने खबू वाहवाही पायी। वहीं सम्मेलन की समाप्ति के बाद राजकीय यात्रा पर भारत आए सऊदी क्राउन प्रिंस की उपस्थिति में तमाम समझौते इस सम्मेलन के एक बोनस की तरह हैं। सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते सदाबहार रहे हैं। लेकिन निवेश व अन्य मोर्चों पर साझेदारी ने रिश्तों को और गहराई दी है। वास्तव में हाल के वर्षों में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो निकटता बढ़ी है, उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी नजर आया है। हाल के दिनों में अमेरिका से सऊदी अरब के रिश्तों में खटास जगजाहिर है। जी-20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन व प्रिंस सलमान के मिले हाथों को थामे प्रधानमंत्री के हाथों वाला चित्र अंतर्राष्ट्रीय राजनय में चर्चा का विषय रहा। बहरहाल, भारत और सऊदी अरब के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के ठोस परिणाम सामने आए। इस दौरान सार्वजनिक उपक्रमों व निजी क्षेत्रों के बीच पचास महत्वपूर्ण समझौते हुए। हाल के दिनों में जहां भारत से सऊदी अरब को निर्यात बढ़ा, वहीं आयात में भी खासी वृद्धि हुई। ऐसे दौर में जब कोरोना संकट व रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। इससे पहले भी जब 2019 में प्रिंस सलमान भारत आए थे तो उन्होंने सौ अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की थी। अब इस दिशा में साझा टारस्क फोर्स बनाने की घोषणा दिल्ली वार्ता में हुई है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी खाड़ी देशों से बेहतर संबंध बनाने को अपनी प्राथमिकता देते रहे हैं। वे पिछले कुछ वर्षों में दो बार सऊदी अरब का दौरा भी कर चुके हैं। निस्संदेह, मध्यपूर्व में एक बड़ी ताकत होने के कारण सऊदी अरब से बेहतर रिश्तों के खास मायने हैं। कहीं न कहीं इस्लामिक देशों पर खासे प्रभाव वाले सऊदी अरब को भारत पाक पर दबाव बनाने वाले सहयोगी के रूप में भी देखता है। जिसके जरिये पाक के निरंकुश व्यवहार पर नकेल करसी जा सके। हाल के वर्षों में भारत-सऊदी अरब के बीच सालाना व्यापार का पांच हजार करोड़ डॉलर तक पहुंचना दोनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों की बानगी है। कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने पिछले दिनों सऊदी अरब में दो सौ करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। वहीं सऊदी अरब की कंपनियां दो साल पहले तक तीन सौ करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत में कर चुकी थीं। दरअसल, प्रिंस सलमान सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करके उस टैग को हटाना चाहते हैं कि वह सिर्फ तेल से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। तभी वे उत्पादन, पर्यटन, तकनीक आदि के क्षेत्र में बड़े निवेश को आमत्रित करते हुए भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। भारत भी सऊदी अरब के लिये उभरते बाजार के रूप में निवेश का भरोसेमंद स्थल है। जब भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर बढ़ने का उदघोष करता है तो निवेशकों के लिये एक भरोसा पैदा होता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रतिभाओं व तकनीशियनों से भी सऊदी अरब को खासी उम्मीद है। जिसके जरिये वह अपने 2030 के विजन को यथार्थ में बदल सके। जिसमें उसकी महत्वाकांक्षी 'इको-सिटी' बसाये जाने की योजना भी शामिल है। यहीं वजह कि ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनने को आतुर सऊदी अरब भारत जैसे देशों से संबंध मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में सऊदी अरब के सहयोग से बनने वाला महत्वाकांक्षी 'वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट' दोनों देशों के बेहतर होते संबंधों की बानगी है। दूसरी ओर जी-20 सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री ने 'इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर' की घोषणा की तो इसमें सऊदी अरब की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। इस प्रोजेक्ट को चीन के 'बेल्ट एंड रोड परियोजना' के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल, प्रिंस सलमान की वह टिप्पणी सुखद अहसास कराती है जिसमें उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब की आबादी का सात फीसदी हिस्सा भारतीयों का है, जिनका वे अपने नागरिकों की तरह ख्याल रखते हैं। निस्संदेह, दोनों देशों के बीच हुए हालिया समझौते संबंधों को नये आयाम देंगे।

लोकतंत्र में श्राप का क्या काम?

भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सदस्य प्रज्ञा ठाकुर, फिर से श्राप देती नजर आ रही हैं। इस बार वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि पर बरस पड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में सनातन धर्म को मलेरिया और कोरोना के वायरस जैसा बतलाते हुए कहा था कि ये जितनी जलदी नष्ट हो जायें उतना ही अच्छा। मंगलवार को भोपाल की भेल (बीएचईएल) कंपनी के गेट पर वेतन वृद्धि की मांग पर कर रहे ठेका श्रमिकों का अनशन खत्म करवाने पहुंची थीं। अपने भाषण में उन्होंने जूनियर स्टालिन के बयान को अभद्र तो बताया ही, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मटन बनाये जाने पर उन्हें विधर्मी भी करार दिया। प्रज्ञा ने कहा कि, ये लोग (राहुल) कुछ भी कर सकते हैं—जेनेज व तिलक लगा लेते हैं तो क्रॉस भी पहन सकते हैं। उनका गुस्सा यहीं तक नहीं ठहरा। उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा कि श्वे कहां के तोपचंद हैं जो किसी को श्राप देंगे? शुरजेवाला ने भाजपा के मतदाताओं को राक्षसी प्रवृत्ति का बतलाया था। उदयनिधि के बयान के बाद द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेता ए राजा ने सनातन को कुछ रोग व एड्स जैसा बतला दिया। एकटर प्रकाश राज ने भी सनातन धर्म की तुलना डेंगू से कर दी थी। इन सभी को एकमुश्त श्राप देते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि श्रप्ताकाश राज नायक नहीं, खलनायक हैं। उनका कहना था कि शजिसे यह नहीं पता कि वह कहां रहता है और किसके खिलाफ बोल रहा है, वह खलनाक ही हो सकता है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि शजिसने सनातन धर्म को जैसा कहा, वह वैसा ही भोगे। जिसने इस धर्म को डेंगू मिले, जिसने मलेरिया कहा उसे वही मिले और जिसने उसे कुछ रोग कहा उसे वही वही प्राप्त हो। उन्होंने इन सभी बयान देने वालों को उनके द्वारा उल्लेखित वीमारियां भरपूर मिलने की बात कही। प्रज्ञा ठाकुर द्वारा इस प्रकार किसी को श्राप देने का मामला पहला नहीं है। मालेगांव बम विस्फोट कांड की आरोपी प्रज्ञा ने महाराष्ट्र पुलिस के विशेष जांच दल प्रमुख हेमन्त करकरे के बारे में 2019 में बयान दिया था कि उनकी (करकरे) मौत इसलिये हुई थी वयोंकि उन्होंने करकरे को श्राप दिया था। साथी के अनुसार पुलिस कस्टडी में जांच के दौरान करकरे ने उन्हें प्रताड़ित किया था। वे कहती हैं— मैंने करकरे को कहा था कि तेरा सर्वनाश होगा। मेरे श्राप के कुछ ही दिनों के बाद 2008 में करकरे आतंकवादियों के हाथों मुर्बई हमले के दौरान मारे गये थे। वैसे जब इस पर हंगामा हुआ तो उसका देश भर में विरोध हुआ था। अनेक वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने इस पर कड़ी आपति जताई थी। इसके दबाव में उन्होंने अपना बयान यह कहकर वापस ले लिया कि दम्भमें देश के टम्पनों को फायदा द्या जाए।

बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट नीति पर हो पुनर्विचार

पंकज चतुर्वेदी

हिमाचल प्रदेश का बड़ा हिस्सा अचानक आई तेज बरसात और जमीन खिसकने से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जहां आपदा आई नहीं वहां के लोग भी आशंका में जी रहे हैं। राज्य के नेशनल हाईवे व अन्य सड़कों के यातायात पर बुरी तरह असर हुआ। कई सौ गांवों में बिजली व जल आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गयी थी। सैकड़ों लोग मारे गये व कई लापता हुए। अनुमानित हजारों करोड़ का नुकसान है। पहाड़ों के धसने से घर, खेत से लेकर सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उससे उबरने में राज्य को सालों लगेंगे। गंभीरता से देखें तो ये हालात भले ही आपदा से बने हों लेकिन इन आपदाओं को बुलाने में इंसान की भूमिका भी कम नहीं। जब दुनियाभर के शोध कह रहे थे कि हिमालय पर्वत जैसे युवा पहाड़ पर पानी को रोकने, जलाशय और सुरंगें बनाने के लिए विस्फोटक के इस्तेमाल के अंजाम अच्छे नहीं होंगे, तब हिमाचल की जल द्वारा आओं पर छोटे-बड़े बिजली संयंत्र लगा कर उसे विकास का प्रतिमान बताया जा रहा था। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसरो द्वारा तैयार देश के भूख्यलन नक्शे में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों को बेहद संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया

है। देश के कुल 147 ऐसे जिलों में संवेदनशीलता की दृष्टि से मंडी को 16वें स्थान पर रखा गया है। यह आंकड़ा और चेतावनी फाइल में कैद रही और इस बार मंडी में तबाही सामने आ गयी। ठीक यहाँ हाल शिमला का हुआ जिसका स्थान इस सूची में 61वें नम्बर पर दर्ज है। प्रदेश में 17,120 स्थान भूस्खलन संभावित क्षेत्र अंकित हैं, जिनमें से 675 बेहद संवेदनशील मूलभूत सुविधाओं और घनी आबादी के करीब हैं। इनमें सर्वाधिक स्थान चंबा जिले में हैं, उसके बाद के क्रम में मंडी, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, ऊना, कुल्लू शिमला, सोलन आदि हैं। यहाँ भूस्खलन की दृष्टि से किन्नौर जिले को सबसे खतरनाक माना जाता है। बीते साल भी किन्नौर में दो हादसों में 38 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद किन्नौर जिला में भूस्खलन को लेकर भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के विशेषज्ञों के साथ-साथ आईआईटी, मंडी व रुड़की के विशेषज्ञों ने अध्ययन किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 97.42 प्रतिशत भूस्खलन संभावित है। हिमाचल सरकार की डिजास्टर मैनेजमेंट

यथन
ा में
रती
म से
स्थल
खिम
हैं।
ण ने
न से
वित
हैं।
र में,
रचम
सपा
रहा
होगी
रीका
ं में
धिक
मेगा
दावा
एक
प्रति
केया
प्रदेश
कार्य
सके
पहले
वर्ष
वाट
परिद्युत
शुरू
हुई थी। इसके बाद वर्ष 1911
औपचारिक रूप से शिमला फै
के चाबा में 1.75 मेगावाट क्षमता
का बिजली संयंत्र शुरू हुआ फै
ब्रिटिश भारत की बिजली जरूरत
को पूरा करने के लिए स्थापित
किया गया था। इसके बाद फै
और बिजली संयंत्र लगाने से
संभावनाएं तलाशी जाने लगी।
इसी योजना के तहत मंडी फै
के जोगिन्द्रनगर में 48 मेगावाट
की बड़ी परियोजना का नियन्त्रण
कार्य शुरू किया गया जो 1932
में पूरा हुआ। आज हिमाचल
में 130 से अधिक छोटी-बड़ी
बिजली परियोजनाएं चालू
जिनकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता
10,800 मेगावाट से अधिक है। सरकार का इरादा 2025
तक राज्य में 1000 से अधिक जलविद्युत परियोजनाएं लगाने
हैं जो कुल 22,000 मेगावाट क्षमता
की होंगी। इसके लिये सतर्क
व्यास, रावी और पार्वती स्थान
तमाम छोटी-बड़ी नदियों पर
गों की कतार खड़ी कर दी गई है। हिमाचल सरकार की चाही
निर्माणाधीन और प्रस्तावित
परियोजनाओं की कुल क्षमता
3800 मेगावाट से ज्यादा है।
हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन
की चोट कितनी गहरी है, इसका



अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 50 स्थानों पर आईआईटी मंडी द्वारा विकसित आपदा पूर्व सूचना यंत्र लगाये गए हैं। भूस्खलन जैसी आपदा से पहले ये लाल रोशनी के साथ सायरन बजाते हैं लेकिन इस बार आपदा इतनी तेजी से आई कि ये उपकरण काम के नहीं रहे। कई शोध पत्र कह चुके हैं कि हिमाचल में अंधाधुंध जल विद्युत परियोजनाओं से कई दिक्कतें आ रही हैं। पहला इसका भूवैज्ञानिक प्रभाव है, जिसके तहत भूस्खलन, तेजी से मिट्टी का ढहना शामिल है। दूसरा प्रभाव जलभूवैज्ञानिक है जिससे झीलों और भूजल स्रोतों में जल स्तर कम हो रहा है। तीसरा, बिजली परियोजनाओं में नदियों के किनारों पर खुदाई और बह कर आये मलबे के जमा होने से बनों और चरागाहों में जलभराव बढ़ रहा है। चौथा खतरा है, सुरक्षा में कोताही के चलते हादसों की संभावना। सच है कि विकास का पहिया बगैर ऊर्जा के घूम नहीं सकता लेकिन ऊर्जा के लिए ऐसी परियोजनाओं से बचा जाना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश को हादसों का प्रदेश बना दें।

ਜਨਦੰਗ ਫੀ ਅਨਿਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਸ਼ਵਦੰਗ ਅਮਿਕਾਈ

विश्वनाथ सचदेव

हाल ही म सपन्न हुए जो—20
आयोजन की 'शानदार सफलता' के
बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है।
यह बात अपने आप में कम महत्वपूर्ण
नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक
भी यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि
कुछ सदस्य देशों के विरोध के
बावजूद इस सम्मेलन में एक
'सर्वसम्मत' सामूहिक विज्ञप्ति जारी
की जा सकी। भारत से लेकर
अमेरिका तक के कॉरिडोर का मुद्दा
हो या रूस—यूक्रेन का मुद्दा या फिर
अफ्रीकी यूनियन को जी—20 का
सदस्य बनाने का मामला, इन सबको
भारत की दृष्टि से जी—20 की
महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में ही
गिना जायेगा। जहां तक इस पूरे
आयोजन का सवाल है, निश्चित
रूप से यह भव्य और शानदार था।
मजाक में ही सही, पर कहा जा रहा
है कि जी—20 के आगामी मेजबान
के लिए आयोजन की यह भव्यता
एक बड़ी चुनौती बन जायेगी।
आयोजन की समाप्ति पर हमारे प्रधा-
नमंत्री मीटिंग से 'पिछे' आए-

मुझा है जिसे लेकर भारत में, और भारत से बाहर भी, चर्चा हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री प्रेस के सवाल—जवाब से कतराते हैं, यह बात जग—जाहिर है। भाजपा सरकार के दो कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। इन लगभग नौ सालों में प्रधानमंत्री का एक भी प्रेस—सम्मेलन में भाग न लेना चर्चा का ही नहीं, आलोचना का विषय भी बना हुआ है। और यह भी सही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस आलोचना से परेशान होते हुए भी नहीं दिख रहे। लगता है उन्हें विश्वास है कि उनका मीडिया—प्रबंधन इस आलोचना से आसानी से उबर सकता है। दुनिया भर के मीडिया कर्मी इस सम्मेलन को कवर करने के लिए आये हुए थे। सबके पास पूछने के लिए कुछ था। खासकर दुनिया के इतने बड़े—बड़े नेताओं का सम्मेलन मीडिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। उम्मीद की गयी थी कि सम्मेलन की संयुक्त विज्ञप्ति के जारी किये जाने के अवसर पर राष्ट्राध्यक्षों की द्विपक्षीय वार्ताओं के बारे में बड़े नेता मीडिया से मुखातिब होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और कहा यह जा रहा है कि सम्मेलन के मेजबान राष्ट्र भारत ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। भारत—अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया को बहुत उम्मीद थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री रस्से से भीड़िया को संबोधित किर चाहे यह संबोधन प्रमोटरी की अमेरिका यात्रा बहुत हुए एक—एक सवाल जैसा न हो। पर ऐसा कुछ हुआ। यह नहीं बताया जा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आये पत्रकारों को संबोधित का अवसर उन्हें नहीं दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रबंधन अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन प्रेस—वार्ता के लिए तैयार मेजबान राष्ट्र की असहायता कारण ऐसा हो नहीं पाया। मीडिया से राष्ट्रपति बाइडेन की तो की, पर भारत में नहीं, इंडिया में। वहां पहुंचकर उन्होंने यह भी जरूरी समझा कि उन्होंने सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री से हुई बातचीत में प्रेस की भी और मानवाधिकारों की रक्षा भी उठाया था। भारत की अभी तक इस बारे में कुछ कहा गया है, पर अपने आप बात कम महत्वपूर्ण नहीं। भारत और अमेरिका के नेता इस विषय पर बातचीत की अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी जाकर बताया कि उन्होंने प्रमोटरी से ‘मानवीय अधिकारों की स्वतंत्रता और सिविल संस्कृति के सम्मान’ करने की बात

हेहक रेंगे— मंत्री पैरान क्यों नहीं। कि साथ करने आया। एसी , पर के अपने बात शिया नहा—20 मोदी उत्तरता मुद्दा र से नहीं यह कि मौजों ने की। अम में मनमंत्री प्रेस गयटी कही थी। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका की राजकीय र पर गये थे तब भी वार्ता के दौ यह मुद्दे उठे थे और बाद में का विषय भी बने थे। प्रेस स्वतंत्रता और मानवाधिकारों रक्षा का सवाल जनतांत्रिक और आदर्शों के साथ जुड़ा अमेरिका और भारत दोनों जनतांत्रिक देश हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के संदर्भ में इन देश अपनी प्रतिबद्धता घोषित करहते हैं। दोनों देशों के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। इसीलिए यह बात थोड़ी अलगी थी जब बड़े नेताओं ने मीडिया से सीधे बात करने में असमर्थता दिखायी। आखिर क्या विवशता थी जिसके चलावे इस आशय का निर्णय किया गया। इस जी—20 सम्मेलन में मीडिया के लिए विशेष प्रबंध किये गये। इस बात की भी सावधानी बढ़ गयी थी कि मीडिया को दी गयी सुविधाओं का समुचित प्रचार लेकिन सम्मेलन के आखिरी प्रधानमंत्री मोदी का मीडियाकर्फूल के सामने से हाथ हिलाते हुए निजाना यह भी बता रहा था कि कुछ है जो हमारे प्रधानमंत्री मीडिया से परहेज रखने के विवश करता है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का दूसरा कार्यवाही



दोनों
करते
यानों
गया
जीव
डेया
पनी
वह
लते
या।
डेया
थे।
रती
गयी
हो।
दिन
मेंयों
कल
कहीं
को
लिए
मोदी
काल
समाप्त होने जा रहा है। वे शायद दुनिया के अकेले ऐसे जनतांत्रिक नेता होंगे जिसने प्रेस से एक निश्चित दूरी बनाये रखना जरूरी समझा है। प्रधानमंत्री की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई पिछले नौ—दस सालों में। एक बार जरूर आये थे प्रधानमंत्री पत्रकारों के समक्ष, पर तब उनसे पूछे गये सवालों के जवाब गृहमंत्री अमित शाह ही दे रहे थे। उस 'प्रेस—वार्ता' में प्रधानमंत्री ने पूरा समय चुप्पी साध रखी थी। यहां यह कहना जरूरी है कि अपने इस लंबे कार्य—काल में प्रधानमंत्री जी ने कुछ पत्रकारों से बात अवश्य की है। टीवी पर भी बात करते हुए दिखे हैं प्रधानमंत्री। पर कुल मिलाकर यह ऐसे ही पत्रकार थे जो उनसे यह जानना चाह रहे थे कि 'वह आम काटकर खाना पसंद करते हैं या चूस कर!' यह विस्मय का चिह्न हटना ही चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता और महता जनतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न और जरूरी अंग है। न इसकी उपेक्षा होनी चाहिए, न इसका दुरुपयोग। दुर्भाग्य से जी—20 के इस शानदार आयोजन में यह कभी कहीं न कहीं खलने वाली है। जनतंत्र की जननी कहते हैं हम अपने देश को। आयोजन के दौरान राजधानी दिल्ली में इस आशय के ढेरों पोस्टर भी लगे थे। लेकिन स्वतंत्र और सजग प्रेस की यह जनतांत्रिक शर्त कहीं न कहीं अधूरी रह गयी। इस 'भव्य' और 'सफल' आयोजन के कर्ता—धर्ताओं को यह अवश्य बताना चाहिए कि अमेरिकी पत्रकारों को भी अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करने के लिए वियतनाम तक पहुंचने का इंतजार क्यों करना पड़ा? और यह भी कि अमेरिकी प्रवक्ता का यह कहना कितना उचित है कि भारत के प्रधानमंत्री— कार्यालय ने अनुमति नहीं दी थी, अन्यथा राष्ट्रपति बाइडेन तो प्रेस— वार्ता के लिए तैयार थे?

गौरवशाली हिंदी भाषा, साहित्य का वैश्विक आकाश

संजाव ठाकुर
दिंदी भाषा

हिंदी भाषा कराड़िया भारतीय के दिलों में बसी हुई भाषा है। हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहां भी है ओष्ठीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। हिंदी की सार्वभौमिक स्वीकार्यता के कारण ही भारतीय राजनेताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था। उल्लेखनीय है कि हिंदी भाषा विदेशों में जितनी फल फूल रही है बल्कि हिंदी बोलने वाले भारतवंशी कई देशों के राष्ट्र प्रमुख भी हैं जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, पुर्तगाल के एंटोनियो कोष्टा प्रधानमंत्री, श्री इरफान गुयाना के राष्ट्रपति, सुरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी, और से सिल के राष्ट्रपति रामखेलावन पदस्थ हैं। इन देशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी हिंदी के

विस्तार का बड़ा माध्यम बना हुआ है। हिंदी मूलतः बड़ी विशाल एवं आसानी से बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली भाषा है। भारत की भौगोलिक विशालता और विविधता के बावजूद हिंदी सर्व स्वीकार्य और देश की सर्व सम्मत भाषा है। यह अलग बात है कि अभी तक संवैधानिक रूप से इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय आंदोलनकारियों ने यह महसूस किया की एकमात्र हिंदी भाषा ही ऐसी भाषा है जो दक्षिण के कुछ क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा है। भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पर हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो भारत में विभिन्न भाषा भाषाई नागरिकों के मध्य विचार विनिमय और संपर्क के लिए एक बड़ा सहारा है। हिंदी के विशाल स्वरूप को मद्देनजर रख पूर्व राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा थिंडी चिरकाल से ऐसी भाषा हड्डी है जिसने मात्र विदशा हान के कारण शब्द का या भाषा का बनानी कियाए यह शब्द हिंदी परिव्रता और व्यापकता के करते हैं। वर्तमान परिस्थिति समय काल में पूरे विश्व करोड़ लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। इसकी सरलता सहजता विश्व के लोगों के प्रभावित भी करती है। फिर विद्वानों, शिक्षाविदों, लेखकों रचनाकारों और युवा लेखकों हिंदी को वैश्विक पहचान में अहम भूमिका भी निभाई नामचीन विद्वान लेखक हिंदी को वैश्विक भाषाई शिख पहुंचाया है। इसी अनुक्रम सितंबर 1949 को संविधान एकमतेन हिंदी को भारत की बनाने का निर्णय लिया गया। सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके निर्णय भी लिया गया था। उन्होंने दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य राजकीय कार्यालयों इसके प्रचार प्रसार एवं प्रत्याचार में

प्रयाग का बढ़ावा दन का हा-
हिंदी भाषा को पूरे विश्व में द्वि-
भाषा के रूप में माना जाता है।
नए वैश्विक स्तर पर अपने च-
के कारण अंग्रेजी भाषा को भी क-
पीछे छोड़ दिया है। आज हिंदी
का कंप्यूटर, इंटरनेट ई बुक, सो-
मीडिया, विज्ञापन, टेलीविजन रो-
आदि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्र-
क्रिया जा रहा है। भारत की विभि-
जनसंख्या विदेशी व्यापारियों के
एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है।
कारण है कि विदेशी कंपनियां 3
सभी विज्ञापनों एवं सामानों में हि-
भाषा का उपयोग कर भारत
जनमानस को अपने उत्पादों
प्रति आकर्षित करना चाहती है।
वजह है कि हिंदी का व्या-
प्रचार—प्रसार भी इसी माध्यम
हो रहा है। विदेशों में भार-
फिल्मों ने भी हिंदी का बड़ा
वृहद प्रचार प्रसार किया है। ब्रिं-
अमेरिका, कनाडा, रूस
निवासरत भारतीय लोग हिंदू-
प्रचार में निरंतर लगे हुए हैं।

